सिवाना रिंग कॉम्प्लेक्स के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त करें- भजनलाल

मुख्यमंत्री भजनलाल की प्रो-एक्टिव अप्रोच से राजस्थान खनन क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है- केन्द्रीय खान मंत्री

जयपुर 19 मई। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राजस्थान खनिज संपदा की दृष्टि से देश में अग्रणी राज्यों में शामिल है तथा प्रदेश के खनन क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं। राज्य में 82

- केन्द्रीय खान व कोयला मंत्री जी. किशन रेड्डी के साथ मुख्यमंत्री भजनलाल ने खान एवं विभाग की बैठक ली। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे यह सुनिश्चित करें कि जिन खनिज ब्लॉक्स की नीलामी हो चुकी है, वहाँ पर शीघ्र उत्पादन कार्य शुरु हो।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा व केन्द्रीय खान एवं कोयला मंत्री जी. किशन रेड्डी ने मंगलवार को मुख्यमंत्री निवास पर खान एवं कोयला विभाग की बैठक को संबोधित किया।

प्रकार के खनिज उपलब्ध हैं और 57 खनिजों का दोहन किया जा रहा है। हमारी सरकार खनन क्षेत्र में पारदर्शिता, नीतिगत सुधार और बुनियादी ढ ांचे में विकास को प्राथमिकता दे रही है।

मुख्यमंत्री मंगलवार को मुख्यमंत्री निवास पर केन्द्रीय खान एवं कोयला मंत्री जी. किशन रेड्डी की उपस्थिति में खान एवं कोयला विभाग की बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सिवाना रिंग कॉम्प्लेक्स प्रदेश में बाड़मेर एवं बालोतरा जिले में लगभग 725 वर्ग किलोमीटर में फैली हुई वृत्ताकार/अर्धवृत्ताकार आग्नेय चट्टानों की संरचना है। सिवाना रिंग कॉम्प्लेक्स एवं सिवाना ग्रेनाइट में रेयरअर्थ एलिमेंट एवं हेवी रेयरअर्थ एलिमेंट उपलब्ध है। साथ ही, आधुनिक तकनीकी एवं स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में इसका राष्ट्रीय महत्व है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सिवाना रिंग कॉम्प्लेक्स के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए प्रदेश में नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाए। वहीं, इस संबंध में खान विभाग एवं संबंधित जिला कलक्टर केन्द्र सरकार के अधिकारियों के साथ बैठक करें, जिससे काम में तेजी आ सके। मुख्यमंत्री ने केन्द्र सरकार से आग्रह किया कि भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा राज्य में चिन्हित एवं अन्वेषित साइट्स की जानकारी राज्य सरकार के साथ साझा करें, जिससे संरक्षण की दृष्टि से उपयुक्त भूमि का अन्य प्रयोजन के लिए आवंटन नहीं हो। उन्होंने पर्यावरण स्वीकृति से जुड़े कार्यों को प्राथमिकता के साथ गति देने के निर्देश दिए और कहा कि जिन खनिज ब्लॉक्स की नीलामी हो चुकी है, वहां पर शीघ्र ही उत्पादन कार्य शुरू करने पर विशेष ध्यान दिया जाए। उन्होंने कहा कि खनन गतिविधियों के लिए खान विभाग के अधिकारी नियमित बैठक कर कार्य योजना बनाएं। इससे खनन कार्य में भविष्य में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं होगी एवं कार्यों की पुनरावृत्ति से बचा जा सकेगा।

केन्द्रीय खान एवं कोयला मंत्री जी. किशन रेड्डी ने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की प्रो-एक्टिव अप्रोच से राजस्थान खनन क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है। राज्य में खनिज संसाधनों के वैज्ञानिक दोहन, निवेश अनुकूल वातावरण तथा पारदर्शी नीतियों के कारण राजस्थान खनन के प्रमुख केन्द्र के रूप में उभर रहा है।

बैठक में अतिरिक्त मुख्य सचिव खान एवं पेट्रोलियम अपर्णा अरोड़ा ने प्रस्तुतीकरण के माध्यम से खनन एवं पेट्रोलियम क्षेत्र में राज्य सरकार की नीतियों, केन्द्र से जुड़े मुद्दों की जानकारी दी। बैठक में मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास तथा केन्द्र एवं राज्य सरकार के अधिकारीगण उपस्थित रहे।

पूर्व मुख्यमंत्री जनरल भुवन चंद्र खंडूरी का निधन

देहरादून, 19 मई। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के वरिष्ठ नेता, पूर्व केन्द्रीय मंत्री एवं उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मेजर जनरल भुवन चंद्र खंडूड़ी का आज सुबह यहां निधन हो गया।

वे 92 वर्ष के थे। उन्होंने पूर्वान्ह करीब सवा ग्यारह बजे यहां मैक्स अस्पताल में अंतिम श्वास ली। उन्हें आयु संबंधी स्वास्थ्य समस्याओं के कारण करीब पंद्रह दिन पहले अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उनकी पुत्री ऋतु खंडूड़ी भूषण उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष हैं, जबकि पुत्र मनीष खंडूड़ी भाजपा के कार्यकर्ता हैं।

- वे 92 वर्ष के थे तथा आयु संबंधी स्वास्थ्य समस्याओं के कारण 15 दिन से अस्पताल में भर्ती थे।

पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में केन्द्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री रहे मेजर जनरल खंडूड़ी के निधन पर राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गहरा शोक व्यक्त किया है। एक्स पर अपने संदेश में मुख्यमंत्री ने कहा, "उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय मेजर जनरल भुवन चंद्र खंडूड़ी (सेवानिवृत्त) जी के निधन का दु:खद समाचार प्राप्त हुआ।

खंडूड़ी का बुधवार को हरिद्वार के खड़खड़ी घाट पर पूरे राजकीय व पुलिस सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा। खंडूड़ी के निधन पर प्रदेश सरकार ने तीन दिन के राजकीय शोक की भी घोषणा की है। उनके अंतिम संस्कार के दिन पूरे राज्य के सरकारी कार्यालय बंद रहेंगे।

अमेरिका -ईरान को मनाने में जुटे हैं अरब देश

कतर, यूएई और सऊदी अरब की कोशिशों के बीच ट्रंप ने हमला टाल दिया है

वाशिंगटन/तेहरान/इस्लामाबाद , 19 मई। दुनिया के प्रमुख और सबसे अहम तेलमार्ग होर्मुज़ जलडमरूमध्य पर खिंची तनाव की तलवारों के बीच कतर, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) और पाकिस्तान, अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौता कराने के प्रयासों पर लगे हुए हैं। मध्यस्थ की भूमिका में विफलता के बावजूद पाकिस्तान ने हार नहीं मानी है। वह अब भी अपने स्तर पर ईरान को मनाने की कोशिश कर रहा है। कतर, सऊदी अरब और यूएई, तीनों मिलकर इस संकट का समाधान निकालने के लिए कूटनीतिक प्रयास कर रहे हैं। तीनों ने अमेरिकी राष्ट्रपति को इस बात के लिए राजी कर लिया है कि वे फिलहाल ईरान पर हमले की अपनी योजना को स्थगित कर दें।

- हालांकि अमेरिका अभी भी ईरान के परमाणु कार्यक्रम को बंद करने की शर्त पर अडा हुआ है।
- इसी बीच पाकिस्तान के गृहमंत्री मोहसिन नकवी तेहरान पहुंचे ताकि शांति वार्ता को पुनः बहाल किया जा सके।

अरबी चैनल अल जजीरा, अमेरिकी चैनल सीबीएस न्यूज और पाकिस्तान के चैनल दुनिया न्यूज की रिपोर्ट में ईरान-अमेरिका के मध्य छिड़े विवाद की सुर्खियों को विस्तार से तरजीह दी गई है। अमेरिका के राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप ने कहा है कि उन्होंने कतर, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात के अनुरोध पर ईरान पर होने वाले नियोजित हमले को टाल दिया है। उन्होंने कहा, "इस समय शांति समझौते को लेकर गंभीर बातचीत चल रही है।" ट्रंप ने सोमवार दोपहर वाइट हाउस में पत्रकारों से कहा कि सऊदी अरब, कतर और यूएई जल्द ही शांति समझौता कराने के लिए किसी समझौते पर पहुंच जाएंगे।

अमेरिकी राष्ट्रपति ने एक बार फिर अपनी मुख्य शर्त पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि ईरान को हर हाल में अपना परमाणु कार्यक्रम छोड़ना होगा। साथ ही कुछ नरमी दिखाते हुए कहा कि अगर पश्चिम एशिया के सहयोगी देश संतुष्ट हो जाते हैं तो अमेरिका को कोई दिक्कत नहीं है। ट्रंप ने कहा कि इसलिए अमेरिका अब मंगलवार को ईरान पर हमला नहीं करेगा। ट्रंप के अनुसार, यह समझौता अमेरिका और मध्य-पूर्व के देशों को स्वीकार्य होगा।

राष्ट्रपति ट्रंप की घोषणा से पहले ईरान ने कहा था कि उसने संभावित शांति समझौते के लिए शर्तों का एक और संशोधित मसौदा भेजा है। बताया जा रहा है कि यह मसौदा पाकिस्तान के जरिये भेजा गया है। ट्रंप के बयान पर ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने कहा, "यह ध्यान रखा जाए कि बातचीत का मतलब आत्मसमर्पण नहीं है। तेहरान गरिमा, अधिकार और राष्ट्र के अधिकारों की रक्षा के साथ इस बातचीत में शामिल होने के लिए तैयार हुआ है।

उधर, पाकिस्तान के गृहमंत्री मोहसिन नकवी तेहरान पहुंचकर ईरान और अमेरिका के बीच रुकी हुई शांति वार्ता को पटरी पर लाने की कोशिश में जुटे हुए हैं। तेहरान में 16 मई से मौजूद नकवी ने कल वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठकें कीं। वह ईरानी राष्ट्रपति, ईरानी संसद के स्पीकर मोहम्मद बाघर गालिबाफ़ और गृहमंत्री एस्कंदर मोमेनी से मिल चुके हैं। ईरान के राष्ट्रपति ने कहा कि इस्लामी देशों के बीच तालमेल और एकजुटता ही टिकाऊ शांति और स्थिरता की नींव बन सकती है।

सख्त ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

प्रधान ने राज्यों में जिला मजिस्ट्रेटों और पुलिस अधीक्षकों के साथ समन्वय बैठकें आयोजित करने को भी कहा, ताकि परीक्षा केन्द्रों की निगरानी मजबूत हो और सभी व्यवस्थाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जा सके।

उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि परीक्षा केन्द्रों पर सतर्कता और सुरक्षा से किसी तरह का समझौता नहीं होना चाहिए। साथ ही छात्रों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए परिवहन, पेयजल और अन्य आवश्यक सुविधाओं की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश भी अधिकारियों को दिए।

पेट्रोल -डीजल कीमतों में वृद्धि के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन

नई दिल्ली, 19 मई। कांग्रेस ने पेट्रोल, डीजल, सीएनजी और रसोई गैस की बढ़ ती कीमतों को लेकर केन्द्र सरकार के खिलाफ बुधवार को दिल्ली में विरोध प्रदर्शन करने का ऐलान किया है। पार्टी के वरिष्ठ नेता और दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अजय माकन के नेतृत्व में यह प्रदर्शन कोटला मुबारकपुर क्षेत्र के पिलिंजी गांव में आयोजित किया जाएगा। कांग्रेस ने अपने अभियान को 'कमर तोड़ महंगाई के खिलाफ हल्ला बोल' नाम दिया है। पार्टी की ओर से बताया गया कि लगातार बढ़ ती ईंधन और रसोई गैस की कीमतों ने आम लोगों का घरेलू बजट बिगाड़ दिया है। महंगाई के कारण मध्यम वर्ग, श्रमिक, ऑटो चालक, टैक्सी चालक और निम्न आय वर्ग के लोग सबसे अधिक प्रभावित हो रहे हैं।

- दिल्ली प्रदेश कांग्रेस बुधवार कोटला मुबारकपुर में विरोध प्रदर्शन करेगी।

पार्टी के अनुसार, यह प्रदर्शन बुधवार, 20 मई को शाम 6:30 बजे कस्तूरबा नगर विधानसभा क्षेत्र स्थित पिलिंजी गांव, कोटला मुबारकपुर में आयोजित होगा। इसमें कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं के अलावा बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों के भी शामिल होने की संभावना जताई गई है।

उल्लेखनीय है कि 15 मई को पेट्रोल और डीजल की कीमतों में प्रति लीटर तीन रुपये तक की बढ़ोतरी की गई थी, जिसके बाद दिल्ली में पेट्रोल 97.77 रुपये और डीजल 90.67 रुपये प्रति लीटर पहुंच गया। इसके बाद सीएनजी की कीमतों में भी लगातार दो चरणों में कुल तीन रुपये प्रति किलोग्राम की वृद्धि हुई। पहले 15 मई को दो रुपये प्रति किलोग्राम और फिर 18-19 मई के बीच एक रुपये प्रति किलोग्राम की अतिरिक्त बढ़ोतरी की गई।

दिल्ली में निर्माण ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

कर 10-बिल्डिंग वाले कॉमन सेंट्रल सचिवालय में बदल दिया जाएगा, जिसमें सभी केन्द्रीय मंत्रालयों के कार्यालय होंगे। अब तक तीन भवन पूरे हो चुके हैं, नया संसद भवन, उपराष्ट्रपति एनक्लेव और प्रधानमंत्री कार्यालय परिसर सेवा तीर्थ। कृषि भवन और शास्त्री भवन को ध्वस्त किया जाएगा, जबकि आईजीएनसीए और रक्षा भवन पहले ही ध्वस्त हो किये जा चुके हैं। नॉर्थ और साउथ ब्लॉक, जो स्वतंत्रता पूर्व काल के हैं, को खाली कर नए राष्ट्रीय संग्रहालय में परिवर्तित किया जा रहा है।

सीएसएस 1, 2 और 3 अब तक पूरे हो चुके हैं, जबकि सीएसएस 10 (कर्तव्य भवन) को इस साल सितंबर तक पूरा करने का लक्ष्य है। सीएसएस 6 और 7 को मार्च 2027 तक, सीएसएस 8 और 9 दिसंबर 2027 तक और सीएसएस 4 और 5 अप्रैल 2028 तक तैयार करने की योजना है। पूरे प्रोजेक्ट को अप्रैल 2028 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।

मंदिरों पर सरकारी ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

बैंच ने 1 अप्रैल, 2025 के आदेश में कहा था, "संबंधित राज्यों के हिंदू धार्मिक संस्थान और चैरिटेबल एंडाओमेंट्स अधिनियम की विभिन्न धाराओं को चुनौती दिए जाने के दृष्टिगत, हम पाते हैं कि याचिकाकर्ताओं को उक्त धाराओं को चुनौती देने के लिए संबंधित उच्च न्यायालयों के पास जाने की अनुमति दी जा सकती है। यह नोट किया गया है कि इन याचिकाओं में चुनौती दी गई धाराएँ केवल तमिलनाडु हिंदू धार्मिक और चैरिटेबल एंडाओमेंट्स अधिनियम, 1959 तक ही सीमित नहीं हैं, बल्कि इनमें पुडुचेरी अधिनियम, 1932 और आंध्र प्रदेश चैरिटेबल और हिंदू धार्मिक एंडाओमेंट्स अधिनियम, 1987 भी शामिल हैं।"

'ग्रेट निकोबार ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

जयराम रमेश ने सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर लिखा कि भारत को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों पर गर्व है, लेकिन यूनेस्को के विश्व जैवमंडलीय आरक्षित क्षेत्र नेटवर्क का महत्व भी उतना ही अधिक है। उन्होंने कहा कि इनका उद्देश्य पारिस्थितिक और सांस्कृतिक विविधता का संरक्षण करना है। भारत में 18 अधिसूचित जैवमंडलीय आरक्षित क्षेत्र हैं, जिनमें से 13 को अंतरराष्ट्रीय मान्यता प्राप्त है और उन्हें यूनेस्को के विश्व नेटवर्क में शामिल किया गया है। ग्रेट निकोबार जैवमंडलीय आरक्षित क्षेत्र भी इन्हीं 13 क्षेत्रों में शामिल है, जिसकी घोषणा वर्ष 2013 में हुई थी।

कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया कि अब यही संरक्षित क्षेत्र केंद्र सरकार की ग्रेट निकोबार द्वीप परियोजना के कारण गंभीर खतरे में है। यह परियोजना अव्यवस्थित और व्यावसायिक हितों से प्रेरित है तथा इससे संवेदनशील पारिस्थितिक तंत्र को भारी नुकसान पहुंच सकता है।

पीडब्ल्यूडी के 3 ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

और जापाकॉलोनी संपर्क सड़कों के निर्माण में घटिया सामग्री उपयोग करने, निर्माण के दौरान ही सड़कें टूटने, अधूरे कार्य को पूर्ण दिखाकर भुगतान लेने और बिना कार्य किए बिल भुगतान करने की शिकायत मिली थी। इस शिकायत के आधार पर एसीबी चौकी प्रतापगढ़ द्वारा 19 जुलाई 2013 को आकस्मिक जांच की गई। जिसके बाद 18 नवंबर 2013 को मामला दर्ज किया गया। मामले की जांच अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विजय स्वर्णकार ने की।

जांच में तत्कालीन अधिशाषी अभियंता सायरमल मीणा, एन.एल. परमार, गिरधारी लाल वर्मा तथा संवेदक विनोद कोडिया की मिलीभगत से राज्य सरकार को 11 लाख 78 हजार 752 रुपए की आर्थिक हानि पहुंचाना प्रमाणित पाया गया।

एसीबी मुख्यालय द्वारा चालान पेश करने का निर्णय लेने के बाद राज्य सरकार से अभियोजन स्वीकृति जारी हुई। इसके बाद चारों आरोपितों को 18 मई को गिरफ्तार कर 19 मई को न्यायालय में पेश किया गया।

देश में अब आर्थिक तूफान आने वाला है- राहुल गांधी

रायबरेली, 19 मई। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी मंगलवार को अपने दो दिवसीय उत्तर प्रदेश दौरे के पहले दिन रायबरेली में कहा कि देश में अब आर्थिक तूफ़ान आने वाला है। प्रधानमंत्री मोदी ने जो ढ ांचा बनाया था, वह टूटने वाला है।

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल ने रायबरेली में पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि किसान, छोटे व्यापारी, आम आदमी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। प्रधानमंत्री ख़ुद विदेश जा रहे हैं, जबकि दूसरों को जाने से रोक रहे हैं।

- अपने संसदीय क्षेत्र रायबरेली में उन्होंने कहा प्रधानमंत्री खुद विदेश जा रहे हैं, दूसरो को रोक रहे हैं

दरअसल, राहुल गांधी रायबरेली संसदीय क्षेत्र के दो दिवसीय दौरे पर मंगलवार को रायबरेली पहुंचे हैं। यहां कार्यकर्ताओं ने चूरूवा बॉर्डर पर राहुल गांधी का भव्य स्वागत किया। चूरूवा बॉर्डर पर स्थित हनुमान मंदिर पर उन्होंने मत्था टेका और आशीर्वाद लिया। इस दौरान बाहर मौजूद कार्यकर्ता उनके पक्ष में नारेबाज़ी कर रहे थे। राहुल इसके बाद बछरावां पहुंचे। भक्तिन खेड़ा गाँव में सांसद निधि से बने बारात घर का उद्घाटन किया। 15 लाख की लागत से बने इस बारात घर का शिलान्यास भी राहुल ने किया था। इसके अलावा राहुल गांधी अन्य कई कार्यक्रमों में भाग लेंगे। यहां वे लोगों से सीधे रूबरू होंगे तथा कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। राहुल गांधी का लालगंज में महिलाओं के साथ बैठक कर संवाद करने का कार्यक्रम है।

आरजी कर अस्पताल के पूर्व प्राचार्य पर मुकदमा चलेगा

कोलकाता, 19 मई। आरजी कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में चिकित्सक-छात्रा के कथित दुष्कर्म और हत्या मामले में राज्य सरकार ने अस्पताल के पूर्व प्राचार्य संदीप घोष के खिलाफ अभियोजन चलाने की अनुमति प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को दे दी है। मुख्यमंत्री शुभेन्दु अधिकारी ने सोमवार रात एक्स पर इसकी जानकारी देते हुए इसे न्याय की दिशा में एक महत्वपूर्ण और सकारात्मक कदम बताया।

अमेरिका भारत को अपाचे हैलीकॉप्टर व उसके उपकरण बेचेगा

नई दिल्ली, 19 मई। अमेरिका के विदेश विभाग ने भारत को अपाचे हेलीकॉप्टर, सपोर्ट सेवाएं और संबंधित उपकरणों की संभावित विदेशी सैन्य बिक्री (एफएमएस) को मंजूरी दे दी है। इसकी अनुमानित लागत 198.2 मिलियन अमेरिकी डॉलर है।

- अमेरिकी विदेश विभाग ने 198.9 मिलियन यूएस डॉलर की विदेशी सैन्य बिक्री को मंजूरी दी।

अमेरिकी विदेश विभाग के राजनीतिक-सैन्य मामलों के ब्यूरो की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार, भारत सरकार ने एएच-64ई अपाचे हेलीकॉप्टरों के रखरखाव और संचालन सहायता सेवाएं, अमेरिकी सरकार और ठेकेदारों की इंजीनियरिंग, तकनीकी एवं लॉजिस्टिक सहायता सेवाएं, तकनीकी डेटा एवं प्रकाशन, कर्मियों का प्रशिक्षण तथा अन्य संबंधित लॉजिस्टिक और प्रोग्राम सहायता सेवाओं की खरीद का अनुरोध किया है।

अमेरिका ने कहा कि यह प्रस्तावित बिक्री भारत-अमेरिका रणनीतिक संबंधों को और मजबूत करने तथा एक प्रमुख रक्षा साझेदार की सुरक्षा क्षमता बढ़ ाने में मदद करेगी। बयान में कहा गया कि भारत हिंद-प्रशांत और दक्षिण एशिया क्षेत्र में राजनीतिक स्थिरता, शांति और आर्थिक प्रगति के लिए एक महत्वपूर्ण शक्ति बना हुआ है।

अमेरिकी विदेश विभाग के अनुसार, प्रस्तावित सौदे से भारत की वर्तमान और भविष्य के खतरों से निपटने की क्षमता मजबूत होगी, उसकी घरेलू सुरक्षा बेहतर होगी और क्षेत्रीय खतरों के खिलाफ प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी। भारत को इन उपकरणों और सेवाओं को अपनी सेना में शामिल करने में कोई कठिनाई नहीं होगी।

बयान में यह भी कहा गया कि इस उपकरण और सहायता की प्रस्तावित बिक्री से क्षेत्र में मौजूदा सैन्य संतुलन पर कोई असर नहीं पड़ेगा।

इस सौदे के प्रमुख ठेकेदार बोइंग और लॉकहीड मार्टिन होंगे। बोइंग का मुख्यालय वर्जीनिया के आर्लिंगटन में और लॉकहीड मार्टिन का मुख्यालय फ्लोरिडा के ऑरलैंडो में स्थित है।

रिपब्लिकन पार्टी में राजनैतिक ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

भाषण में कैसिडी ने, एक ही व्यक्ति के हाथ में सत्ता सिमटने के खतरे को लेकर चेतावनी दी। उन्होंने कहा, "हमारा देश किसी एक व्यक्ति के बारे में नहीं है।" उन्होंने यह भी कहा कि जो नेता सत्ता के जरिए दूसरों को नियंत्रित करना चाहते हैं, वे देश की नहीं, बल्कि खुद की सेवा कर रहे हैं। फिर भी कैसिडी के शब्द उस सच्चाई को दिखाते हैं, जिसने अब रिपब्लिकन व्यवस्था को पूरी तरह बदल दिया है।

सीनेटर लिंडसे ग्रैहम ने राष्ट्रीय टीवी पर साफ शब्दों में कहा, "इस पार्टी में ट्रंप के एजेंडे को खत्म करने की कोई गुंजाइश नहीं है।"

रिपब्लिकन पार्टी के चरित्र में यह चीज एक बहुत बड़ा बदलाव दर्शाती है। पहले की पीढ़ियों के रिपब्लिकन नेता विचारधारा से प्रेरित होते थे - छोटी सरकार, वित्तीय सख्ती, आक्रामक विदेश नीति या सामाजिक रूढ़िवाद जैसे मुद्दे उनकी पहचान थे। डैमोक्रैट्स इनमें से कई विचारों से असहमत थे, लेकिन पार्टी फिर भी कुछ पहचान योग्य सिद्धांतों के आधार पर चलती थी।

आलोचकों का कहना है कि आज पार्टी का मुख्य उद्देश्य विचारधारा नहीं, बल्कि ट्रंप के प्रति व्यक्तिगत वफादारी बन गया है।

विडंबना यह है कि रिपब्लिकन वोटरों के कुछ वर्ग स्वयं भी बहुत असहज महसूस कर रहे हैं। पारंपरिक कंज़र्वेटिव्ज़ ट्रंप द्वारा कार्यकारी शक्तियों के व्यापक इस्तेमाल से चिंतित हैं। वित्तीय अनुशासन में विश्वास रखने वाले लोग बढ़ते घाटे और सरकारी खर्च से परेशान हैं। "अमेरिका फर्स्ट" समर्थक मतदाता विदेशी सैन्य हस्तक्षेप का विरोध कर रहे हैं और एप्स्टीन फाइल्स सहित, अधिक पारदर्शिता की मांग कर रहे हैं।

फिर भी चुने हुए रिपब्लिकन नेता ज्यादातर चुप हैं, क्योंकि उनका राजनीतिक भविष्य ट्रंप की स्वीकृति पर निर्भर करता है।

इसी वजह से अमेरिका के पूर्व श्रम मंत्री रॉबर्ट राइश जैसे टिप्पणीकार एक ज्यादा गंभीर सवाल उठा रहे हैं: क्या रिपब्लिकन व्यवस्था, ट्रंप की तेजी से अराजक होती राजनीति में भागीदार बन गई है?

रॉबर्ट राइश का कहना है कि ट्रंप के प्रति वफादारी का मतलब अब उन दावों को स्वीकार करना हो गया है, जिन्हें अदालतों और संस्थाओं द्वारा व्यापक रुप से खारिज कर दिया गया है, जिनमें यह दावा भी शामिल है कि 2020 का चुनाव धांधली से हुआ था। इसमें विवादित इमिग्रेशन कार्यवाही, आक्रामक फॉरेन पॉलिसी एक्शन और राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ स्टेट पावर के इस्तेमाल का समर्थन भी शामिल है।

आलोचक ट्रंप पर यह आरोप भी लगाते हैं कि उन्होंने सार्वजनिक पद और निजी फायदे के बीच की रेखा धुंधली कर दी है।

उन पर बिना निविदा वाले ठेके देने, पारिवारिक कारोबारी हितों को बढ़ावा देने, विदेशी उपहार स्वीकार करने और संस्थागत परंपराओं को बार-बार नजरअंदाज करने के आरोप लगाए जाते रहे हैं।

राइश और कई ट्रंप विरोधी कंज़रवेटिव्स के लिए चिंता अब सिर्फ विचारधारा तक सीमित नहीं रह गई है। असली सवाल यह है कि क्या रिपब्लिकन पार्टी अब एक स्वतंत्र राजनीतिक संस्था की तरह काम करना बंद कर चुकी है और एक ऐसे संगठन में बदल गई है, जो केवल एक व्यक्ति की सत्ता, हितों और राजनीतिक अस्तित्व के इर्द-गिर्द खड़ा है।

तृणमूल कांग्रेस में ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

नहीं किया है। निगम के नोटिस में, बिना आधिकारिक अनुमति के, लगाए गए एस्केलेटर और लिफ्ट पर आपत्ति जताई गई है

कम-से-कम एक पार्षद अभिषेक बनर्जी के निर्माण का बचाव करने से पहले ही इनकार कर चुका है। अगर और पार्षद इस्तीफा देते हैं, तो नगर निगम में तय समय से पहले नए चुनाव कराने की स्थिति बन सकती है। कोलकाता नगर निगम के मेयर फिरहाद हाकिम ने कालीघाट क्षेत्र में स्थित अभिषेक बनर्जी के 188 हरीश मुखर्जी स्ट्रीट वाले घर को लेकर नगर निगम द्वारा जारी कई नोटिसों पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। नोटिस में एस्केलेटर, लिफ्ट और सार्वजनिक जमीन पर कथित अतिक्रमण को हटाने की बात कही गई है। फिरहाद हाकिम और कई अन्य नेताओं ने भी अभिषेक बनर्जी की संपत्ति का बचाव करने से इनकार कर दिया है। ऐसी स्थिति बन सकती है कि तृणमूल कांग्रेस द्वारा संचालित कोलकाता नगर निगम और उसी पार्टी के पार्षद अभिषेक की संपत्ति को गिराने की कार्रवाई करें।

टीएमसी नगर अध्यक्ष देबलीना बिस्वास ने नोटिस जारी होने के बाद अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। बताया जा रहा है कि उनसे नगर निगम के तोड़फोड़ वाले इस नोटिस के खिलाफ सड़क पर प्रदर्शन करने को कहा गया था। टीएमसी के कई अन्य नेता और कार्यकर्ता भी अब बेचैन दिखाई दे रहे हैं और पार्टी मामलों में अभिषेक बनर्जी की भूमिका को लेकर खुलकर विरोध जता रहे हैं। आरोप लगाए जा रहे हैं कि पार्टी प्रबंधन और टिकट बांटने की प्रक्रिया का अत्यधिक "कॉरपोरेटाइजेशन" हो गया है।

अब कई लोग अभिषेक बनर्जी के खिलाफ खुलकर आक्रामक रुख अपना रहे हैं और बताया जा रहा है कि अभिषेक सार्वजनिक रूप से सामने आने से बच रहे हैं। अभिषेक ने अभी तक खुद का बचाव करने के लिए कोई खुला कदम नहीं उठाया है।

महेश ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

अपने स्तर पर मामला दर्ज कर पूर्व मंत्री महेश जोशी और संजय बडाया सहित अन्य को गिरफ्तार किया था। तब जोशी को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली थी।

लाहौर में रहमान गली फिर ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

यह प्रोजेक्ट पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की सोच है और इसे उनकी बेटी और वर्तमान पंजाब मुख्यमंत्री मरियम नवाज आगे बढ़ा रही हैं। 50 अरब पाकिस्तानी रुपए के इस प्रोजेक्ट को देश की सबसे महत्वाकांक्षी सांस्कृतिक पुनर्स्थापन कोशिशों में से एक माना जा रहा है। सरकार ने यूरोपीय देशों की तुलना करते हुए कहा है कि पाकिस्तान को भी अपने शहरों के ऐतिहासिक स्वरूप को मिटाने के बजाय, उसे संरक्षित करना चाहिए। हेरिटेज पर्यटन को बढ़ावा देना और उससे होने वाली आय इस बदलाव का एक प्रमुख उद्देश्य है।

यह पहल केवल सड़क नामों तक सीमित नहीं है। शरीफ ने तीन क्रिकेट मैदानों और मिंटो पार्क (आज का ग्रेटर इकबाल पार्क) में पारंपरिक कुश्ती अखाड़े को पुनर्स्थापित करने का प्रस्ताव रखा है। यह कदम 2015 में हुए उस नुकसान की भरपाई के रूप में देखा जा रहा है, जब उनके भाई शहबाज शरीफ, जो उस समय पंजाब के मुख्यमंत्री थे, ने उन मैदानों को शहरी विकास के नाम पर ध्वस्त कर दिया था। शहबाज शरीफ के इस कदम की कड़ी आलोचना सिर्फ क्रिकेटरों ने ही नहीं, इतिहासकारों ने भी की थी। पाकिस्तान कप्तान के पूर्व इंज़ामाम उल हक सहित, कई प्रतिष्ठित खिलाड़ियों ने उस पार्क में स्थित क्लबों में प्रशिक्षण लिया। विभाजन से पहले भारतीय क्रिकेटर लाला अमरनाथ भी वहां खेला करते थे। जब वे 1978 में भारतीय टीम के साथ लाहौर गये, तो वे मिंटो पार्क भी गये और क्रिसेंट क्रिकेट क्लब भी गए, जहाँ उन्होंने कभी प्रशिक्षण लिया था, और वहां के खिलाड़ियों से मिले। ध्वस्त कुश्ती अखाड़े में भी प्रसिद्ध पहलवानों जैसे गामा पहलवान और गूंगा पहलवान के मुकाबले हुए थे और 1947 से पहले, हिंदू हर साल दशहरा मनाने के लिए इस पार्क में ही इकट्ठा होते थे। नाम बदलने की इस पहल को खासतौर पर दिलचस्प बनाने वाली बात यह है कि इसे पाकिस्तान में दशकों से चल रही इस्लामीकरण प्रक्रिया के बावजूद, बहुत कम प्रतिरोध का सामना करना पड़ा। पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों, खासकर हिंदू और सिखों, का इतिहास जबरन धर्मांतरण, संपत्ति पर अतिक्रमण और मंदिरों के ध्वंस से भरा रहा है। हिंदू, सिख, जैन और उपनिवेशकालीन नामों की पुनर्स्थापना लगभग बिना किसी संगठित विरोध के हुई है, जो अपने आप में एक महत्वपूर्ण बात है।

आलोचकों का कहना है कि यह प्रयास अतीत के साथ सच्ची सुलह के बजाय दिखावे पर अधिक आधारित है। पाकिस्तान आतंक वित्तपोषण को लेकर अंतरराष्ट्रीय जांच का सामना कर रहा है, जिससे अर्थव्यवस्था को अरबों का नुकसान हुआ है। लाहौर जैसे प्रमुख सांस्कृतिक शहर में विभाजन पूर्व के नामों की वापसी इस्लामाबाद को यह दिखाने का मौका देती है कि देश चरमपंथ से दूर जा रहा है। पाकिस्तान का यह कदम फायनेंशियल टास्क फोर्स, जिसने पहले पाकिस्तान पर कड़े आर्थिक प्रतिबन्ध लगा दिये थे, के साथ बात करने में लाभदायक हो सकता है।

यह पहल अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ के लिहाज में भी महत्वपूर्ण है, जिस पर पाकिस्तान अपनी आर्थिक सुरक्षा के लिए निर्भर है। आईएमएफ केवल आर्थिक आंकड़ों पर नहीं, बल्कि किसी देश की राजनीतिक स्थिरता और सामाजिक माहौल पर भी नजर रखता है। एक शहर जो अपने बहुसांस्कृतिक हेरिटेज को खुले तौर पर दिखाता है, विदेशी निवेशकों और अंतरराष्ट्रीय कर्जदाताओं को यह संदेश देता है कि पाकिस्तान अब, कम से कम दिखावे में ही सही, सुरक्षित और खुला गंतव्य है।

राष्ट्रदूत (एच.यू.एफ.) के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक सोमेश शर्मा द्वारा वतन प्रेस, सुधर्मा, एम.आई.रोड़, जयपुर एवं सुधर्मा-II, लालकोठी शॉपिंग सेंटर, टोंक रोड़, जयपुर से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक:- राजेश शर्मा । आर.एन.आई. नं. 3641/57, ई-मेल-rastrdut@gmail.com कोटा कार्यालय:-पलायथा हाउस, छत्रपति शिवाजी मार्ग, कोटा। फोन:2386031, 2386032, फैक्स:0744-2386033 बीकानेर कार्यालय:-कुंम्भाना हाउस, हनुमान हत्था, बीकानेर। फोन:2200660, फैक्स: 0151-2527371 उदयपुर कार्यालय:-आयड, मेन रोड आयड, उदयपुर। फोन: 2413092, 2418945, फैक्स: 0294-2410146 अजमेर कार्यालय:-घूघरा घाटी, जयपुर रोड,अजमेर। फोन: 2627612, फैक्स:0145-2624665 जालोर कार्यालय :- जी 1/63, इन्डस्ट्रीयल एरिया, फेस प्रथम, जालोर। फोन: 226422, 226423, फैक्स: 02973-226424 हिण्डौनसिटी कार्यालय :- जी -1-201, रीको औद्योगिक क्षेत्र, हिण्डौनसिटी। फोन: 230200, 230400, फैक्स: 07469-230600 चूरू कार्यालय: एच-150, रीको औद्योगिक क्षेत्र, चूरू, फोन: 256906, 256907, फैक्स:01562-256908